ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

किसान क्यों नहीं बनाते टमाटर से सूप पाउडर?

रविवारीय, 13-19 दिसंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-19, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

हर तीन में से एक स्वास्थ्य केंद्र में हाथ धोने की सुविधा नहीं है

यूनिसेफ और डब्लूएचओ द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया की हर 3 में से एक स्वास्थ्य केंद्र में कचरे को अलग करने की व्यवस्था नहीं है। एक चौथाई अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में साफ जल की व्यवस्था नहीं है जो इन केंद्रों में आने और काम करने वाले 180 करोड़ लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। वहीं 80 करोड़ लोगों को सेवा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अस्पताल जोकि स्वास्थ्य देखभाल का केंद्र बिंदु होते हैं। यदि उनमें ही साफ पानी, हाथ धोने और कचरे के प्रबंधन से जुड़ी सुविधाएं न हो तो इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

इस से भी बदतर बात यह है कि दुनिया के हर तीन में से एक स्वास्थ्य केंद्र में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही 10 फीसदी में पर्याप्त साफ-सफाई और स्वच्छता नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 47 सबसे कम विकसित देशों में स्थिति और भी ज्यादा बदतर है।

अब किसान आंदोलन चढ़ा राजनीति की भेंट

वरीय संवाददाता

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन प्रारंभ में विशुद्ध आंदोलन की तरह लग रहा था। जिसमें किसानों का भय, शंकाएं और मांगे दिख रही थी। लेकिन आंदोलन जैसे जैसे आगे बढता गया वैसे वैसे इसकी विश्वसनीयता और उद्देश्य पर अब पानी फिरते दिख रहा है।

तकरीबन तीन सप्ताह होने चले इस आंदोलन में किसान नेताओं में मांगों के बजाय एक जिद और हठधर्मिता की झलक ज्यादा दिखने लगी है, सरकार की मंशा क्या है? इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी, पर केंद्र सरकार ने बहुत ही चतुराई से इस मामले में यह साबित करने का प्रयास किया है कि वह किसानों की सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने को तैयार है, पर किसान नेाओं की हठधर्मिता के कारण बातचीत आगे नहीं बढ रही है। वहीं किसान नेताओं का सीधा कहना है कि केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस कारण से देश के जनमानस में किसान नेताओं की छवि बातचीत से किसानों की मूल मांगों पर कोई समाधान निकालने के बजाय अड़े रहने वाले जिद्दी नेताओं की तरह हो गयी है। बीच बीच में मीडिया में आकर इनके बयान यह तो जता रहे हैं कि किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हुये हैं, पर यह संदेश भी जा रहा है कि उनकी मंशा निष्कर्ष के बजाय केंद्र सरकार को झुका कर खुद को ताकतवर जताने की है। यानि अब किसान आंदोलन शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक मकसद को साधने वाला आंदोलन बन रहा है।

अपनी राजनीतिक जमीन के खिसकने के भय से जो किसान नेता केंद्र सरकार के साथ थे उन्होंने भी केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है।

दिखावा पड़ रहा भारी

किसान आंदोलन में किसानों के लिये भोजन बन रहा है। मीडिया में यह दिखाया जा रहा है कि आंदोलन में आये किसानों के लिये चौबीसो घंटे लंगर में दाल, खीर, काजू पिस्ता डाल करबन रहा हलवा, पूरी और चाय कॉफी बन रहा है, साथ ही फुट मसाजर मशीन, एसी, इनवर्टर जैसी सुख सुविधाओं के इंतजाम किये गये हैं। इन सुविधाओं को देख कर बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं होकर दलालों और आढ़तियों का पिकनिक है।

जो भी हो, पर यह स्पष्ट है कि सच्चे किसान कृषि कानूनों में सुधार की जो मांग कर रहे थे वह अब गौण होता दिख रहा है।

इन वजहों से आंदोलन का हुआ राजनीतिकरण

यह सच है कि किसान आंदोलन में पंजाब एवं हरियाणा के किसानों के अलावा अन्य राज्य के किसानों की सहभागिता न के बराबर दिख रही है। मीडिया में इस आंदोलन में ज्यादतर चेहरे पंजाब के किसानों के ही दिख रहे हैं। इससे लोगों के मन में यह बात घर कर रही है कि यह आंदोलन क्षेत्र विशेष के किसानों का है, अन्य राज्य के किसान कृषि कानूनों को लेकर परेशान नहीं है।

इसके अलावा कई वामपंथी विचारों से जुड़े किसान यूनियनों के इस आंदोलन में मुखर रहने से आंदोलन पर सच्चे किसानों का होने के बजाय एक खास पंथ विशेष का होने का ठप्पा लग रहा है।

इस आंदोलन में कई ऐसे तत्वों की उपस्थिति मिली है जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त रहे हैं। जैसे कुछ तस्वीरों में शर्जिल इमाम जैसे शख्सियत की रिहाई की मांग की गयी। जिसे केंद्र सरकार ने भी लपक लिया और इसे अराजक देशविरोधी तत्वों का आंदोलन कह कर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वहीं कई राष्ट्रीय चैनलों में इस आंदोलन के तार विदेशों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और आरोप लग रहे हैं कि ये भारत विरोधी तत्व किसान आंदोलन की आड़ में अपना मकसद भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले कनाडा के राष्ट्रपति ट्रूडो के किसान आंदोलन के समर्थन में दिया गया बयान भी इस आंदोलन के खिलाफ ही गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने दावा कर दिया कि कई संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। इसके बाद से यह आंदोलन अब राजनीति की भेंट चढ रहा है

मुख्यमंत्री को मलुटी मंदिरों का मॉडल सौंपा

संवाददाता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को आज दुमका स्थित ऐतिहासिक मलूटी मंदिरों का टेराकोटा मॉडल डॉ सोमनाथ आर्य ने प्रदान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि देखभाल और संरक्षण के अभाव में मलूटी की ऐतिहासि-ाक मंदिरे जर्जर सी हो गई हैं। यहां पहले 108 मंदिर हुआ करती थी लेकिन आज इसकी संख्या घटकर 62 हो गई है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के इस ऐतिहासिक इलाके को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस दिशा में सरकार कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मलूटी स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण और मरम्मत को लेकर सरकार गंभीर है। इसके लिए बहुत जल्द कदम उठाए जाएंगे। ज्ञात हो कि डॉ सोमनाथ आर्य ने पूर्व में मुख्यमंत्री को अपने द्वारा लिखित पुस्तक "बियॉन्ड कंपैरिजन मलूटी" सप्रेम भेंट कर चुके हैं।

किटनाशकों के दुष्प्रभाव को देखने के लिये अब साल में एक बार होगा औचक नीरीक्षण

एजेंसियां

कीटनाशक ईकाइयों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार, साल में एक बार होगा औचक निरीक्षण कीटनाशकों के कारण प्रदूषित होते मिट्टी-पानी और मानव स्वास्थ्य को कम करने के लिए नगरानी प्रोटोकॉल बनाया गया है। सभी कीटनाशक ईकाइयां इस प्रोटोकॉल के दायरे में रहेंगी।

कीटनाशकों के निर्माण की गति तेज हुई है तो इसने मानव स्वास्थ्य और मिट्टी-पानी को प्रदूषित करने में भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। बहरहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश बाद प्रभावी तौर पर कीटनाशकों की निगरानी को लेकर निगरानी तंत्र तैयार हो गया है। इस नए निगरानी तंत्र के प्रोटोकॉल में पर्यावरण प्रदूषण की आशंका के तहत कीटनाश-ाकों का निर्माण करने वाली ईकाईयों का औचक निरीक्षण किया जा सकेगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 26 जून, 2020 को अपने आदेश में चार महीने के भीतर कीटनाशकों की प्रभावी निगरानी के लिए प्रभावी प्रोटोकॉल विकसित करने का आदेश दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए सीपीसीबी ने यह आदेश जारी किया है। एनजीटी ने यह गौर किया था कि उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के आधार पर याचिका में कहा गया था कि अलीगढ़ डिवीजन में करीब सात लाख हेक्टेयर जमीन कीटनाशक के चलते बर्बाद हो गई। वहीं, कीटनाशकों पर निगरानी न होने के कारण इसका मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है।

कीटनाशकों की प्रभावी निगरानी वाले प्रोटोकॉल में तय किया गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियां डॉयरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वरंटीन एंड स्टोरेज (डीपीपीक्यूएस) के साथ संयुक्त तौर पर कीटनाशक ईकाइयों की जांच करेंगी। ईकाइयां संयुक्त समिति के अधीन रहेगी। संयुक्त समिति को कम से कम से कम साल की छमाही पर टेक्निकल ग्रेड वाली ईकाइयां और सालाना स्तर पर फॉर्मुलेट करने वाली कीटनाशक ईकाइयों की औचक जांच करेगी। जांच से पहले किसी भी ईकाई को सूचित नहीं किया जाएगा। यदि कोई आदेश, नियम और कानून का उल्लंघन पाया जाएगा तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति अथवा डीपीपीक्यूएस उस ईकाई पर मौजूदा कानूनों के हिसाब से कार्रवाई करेगा। वहीं, ईकाइयों के इनलेट-आउटलेट, डिस्चार्ज, प्रवाह मानकों का बारीकी से जांच संयुक्त समिति को करना होगा। सैंपल एकत्र करने के साथ ही यह जांचना जरूरी होगा कि कीटनाशक ईकाइयां कहां पर अपना शोधित या गैर शोधित प्रवाह गिरा रही हैं।

यदि जेएलडी यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का दावा है तो इस बात की और सख्ती से जांच करनी होगी। वहीं, पर्यावरण प्रदूषण की संभावना वाली या जहरीली प्रकृति वाली ईकाइयों के डिस्चार्ज बिंदुओं में यह देखना होगा कि कहीं वर्षा जल या बरसाती नालों से उनका कोई प्रवाह नहीं जा रहा जिससे आस-पास पर्यावरण को खतरा हो। या फिर ईकाई में भंडारण के दौरान रिसाव की घटना का जोखिम कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

प्रोटोकॉल के तहत निगरानी तंत्र को कीटनाशक ईकाई के 500 मीटर दायरे में भू-जल यदि कोई जलाशय है तो उसका पानी और मिट्टी की भी जांच करेगा।

कोविड -19 के कारण बच्चों में कुपोषण से मृत्यु का खतरा बढ़ा

एजेंसियां

पहले ही कुपोषण की समस्या से जूझ रहे देशों के लिए कोरोना महामारी ने मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। हाल ही में सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी रिपोर्ट 'न्यूट्रिशन क्रिटिकल' के हवाले से पता चला है कि यदि दुनिया भर में पोषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस महामारी के चलते 2022 तक कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या में 168,000 का इजाफा हो सकता है। साथ ही इसके चलते 5 वर्ष से कम आयु के 93 लाख बच्चों में लम्बाई के अनुपात में वजन कम होगा। इसके करीब दो-तिहाई शिकार दक्षिण एशिया के बच्चे होंगे। 26 लाख अपनी उम्र के लिहाज से ठिगने रह जाएंगे। अनुमान है कि इस महामारी से उपजे आर्थिक संकट के चलते करीब 8 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार होंगे।

कुपोषण के मामले में महिलाओं की शिक्षा भी मायने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार पढ़ी-लिखी मां होने का असर कुपोषण के स्तर पर पड़ता है। जहां शिक्षित माताओं के 24 फीसदी बच्चे कुपोषित थे। वहीं इसके विपरीत कम शिक्षित माताओं के 39.2 फीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार थे।

मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग की समीक्षा की

सरकार किसानों की पसंद को प्रोत्साहित करना चाहती है

किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इस पर कार्ययोजना बने

रांची : राज्य सरकार किसानों की पसंद के अनुरूप उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती है। उनकी पूर्व की आमदनी को बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विभाग किसानों को लाभान्वित करने के लिए समय से पूर्व तैयार रहे, क्योंकि किसान समय के साथ खेती कार्य करते हैं, और अगर उन्हें समय पर लाभ नहीं मिला तो उनकी मेहनत व्यर्थ चली जायेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निदेश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के उत्पादित सब्जियों को अधिक दिनों तक संग्रह करने एवं अधिक मुनाफा देने के लिए कोल्ड रूम के निर्माण को प्राथमिकता दें। यह कार्य अधिक सब्जी उत्पादन करने वाले पंचायत में हो। इसके लिए सभी का ईमानदारी से कार्य करते हुए किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य होना चाहिए। उन्हें बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में कार्य करें।

प्रदूषण में कटौती कस सकती है ग्लोबल वार्मिंग की लगाम

एजेंसियां : एक नये अध्ययन में पता चला है कि कार्बन डाई ऑक्साइड तथाअन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिये मजबूत और तीव्र कदम उठाने से अगले 20 वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग की दर कम करने में मदद मिलेगी। अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिये फौरी कदम उठाने से मौजूदा जिंदगी में ही फायदे मिल सकते हैं। इनके लिये भविष्-य में लम्बा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

वैज्ञानिक पहले ही इस बात से सहमत हैं कि अगर अभी से प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में तीव्र और गहन कटौती की जाए तो इससे इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को सीमित किया जा सकता है। हालांकि अगले कुछ दशकों में अति अल्पकालिक लाभ हासिल करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। खास तौर पर वैश्विक वातावरण और महासागरीय प्रणालियों के कुदरती चक्र, तापमान में भी उतार-चढ़ाव का कारण बन सकते हैं जो जलवायु पर इंसानी गतिविधियों के प्रभावों को अस्थाई रूप से मास्क कर सकते हैं। मगर लीड्स यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न स्रोतों से बड़े पैमाने पर हासिल आंकड़ों को मिलाकर एक नए तरीके से किए गए अध्ययन में प्राकृतिक परिवर्तनशीलता से मानव प्रेरित वार्मिंग को कहीं कम समय के पैमाने पर सुलझाया गया है।

नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित इस अध्ययन में विभिन्न जलवायु मॉडल्स के हजारों सिमुलेशंस के साथ-साथ, महसूस की गई प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के अनेक अनुमानों का इस्तेमाल किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगले दो दशकों में उत्सर्जन में कटौती के विभिन्न स्तर ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट में उभरे तथ्य यह दिखाते हैं कि पैरिस समझौते के अनुरूप प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में कमी लाए जाने से और खासकर वैश्विक तापमान में वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के स्तरों से डेढ़ डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के मकसद से उत्सर्जन में कटौती किए जाने से अगले 20 वर्षों के दौरान वार्मिंग पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक

परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखने के बावजूद यह प्रभाव नजर आएगा।

दरअसल वार्मिंग की दर, जो कि पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है, का खतरा प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में तीव्र और गहन कटौती के साथ जीवाश्म ईंधन पर खासी निर्भरता जारी रखने वाले भविष्य के 'औसत' के मुकाबले 13 गुना कम हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की स्थिति में अगले 20 वर्षों के दौरान वैश्विक तापमान में एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि वर्ष 2050 से काफी पहले ही पेरिस समझौते के तहत व्यक्त की गई प्रतिबद्धता नाकाम साबित होगी।

अध्ययन की मुख्य लेखक डॉक्टर क्रिस्टीन मैक्केना लीड्स में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो हैं और वह यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कॉन्स-ट्रेन परियोजना पर काम कर रही हैं।

मैक्केना ने कहा ''हमारे नतीजे दिखाते हैं कि प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में तीव्र और गहन कटौती करने से सिर्फ भावी पीढ़ियां ही फायदा नहीं महसूस करेंगी। अगर अभी से कदम उठाए गए तो इसका मतलब यह होगा कि हम आने वाले कुछ दशकों में ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही दीर्घकाल में तापमान में बढ़ोत्तरी को सीमित करने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके जरिए हमें उन प्रभावों को टालने में भी मदद मिल सकती है जो तापमान में अधिक तेज और चरम बदलाव के जरिए उत्पन्न हो सकते हैं।

मैक्केना ने कहा ''इस वक्त दुनिया का तापमान प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर हमने फौरी कदम नहीं उठाए तो हम साफ तौर पर पैरिस समझौते का उल्लंघन करने के खतरे से गिर जाएंगे इस रिपोर्ट में उभरे निष्कर्ष सरकारों तथा गैर सरकारी पक्षों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के और मुश्किल लक्ष्य तय करने तथा शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की प्रदूषण मुक्त भरपाई के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेंगे।

सक्षम अमीर देश ही हैं धरती के लिये खतरा

जो देश व्यापार पर अत्यधिक निर्भर हैं, उनके संसाधन उतने ही अधिक खतरे में हैं। शोधकर्ताओं ने 189 देशों के वैश्विक जल, भूमि और ऊर्जा उपयोग की मात्रा निर्धारित की है और दिखाया है कि जो देश व्यापार पर अत्यधिक निर्भर हैं, उनके संसाधन उतने ही अधिक खतरे में हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन में तेजी और चरम मौसम की घटनाओं जैसे कि सूखा बाढ़ अधिक आम होते जा रहे हैं। साथ ही कई देश अपने अधिक खपत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों में पहले से ही दबाव वाले संसाधनों की मांग करते हैं। अमेरिका, चीन और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण पानी की कमी से जल्द ही जूझने वाले हैं। हालांकि, उप-सहारा अफ्रीका के कई देश, जैसे कि केन्या, वास्तव में बहुत कम खतरे का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बड़ी नहीं हैं और खाद्य उत्पादन में अपेक्षाकृत वे आत्मनिर्भर हैं।

अगर इन तथ्यों को सामने रख कर चिंता व्यक्त की जाये तो एक बड़ा तबका इसका उपहास उड़ायेगा। वो कहेगा कि पर्यावरण और जलवायु को बचाने के लिये क्या व्यापार को बंद कर दिया जाये? क्या एक बड़ी आबादी वंचित होकर तपस्या करने लगे? वहीं इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि व्यापार को ही सब कुछ समझने वाले देशों ने इस धरती को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई किसी भी तरह से संभव नहीं। क्या संभव है कि मनुष्य स्वयं पर संयम रख कर भोग की प्रवृत्ति से बच पाये?

जापान में हाथी नहीं होते, पर वहां सदियों से व्यापारियों में एक चलन है कि वो व्यापार कार्यों में हाथी दांत का उपयोग करते हैं। बड़े से बड़े व्यावसायी भी जापान में आम जरूरतों में तो रबर के बने मुहर उपयोग करते हैं, पर महत्वपूर्ण सौदों में वो हाथी दांत से बने मुहर उपयोग करते हैं। इस कारण से जापान में हाथी दांत की बहुत खपत होती है। वो इसके लिये अच्छी कीमत भी अदा करते हैं। लााजमी है इस संस्कृति के कारण हाथियों का शिकार भी होता है।

चीन ने भी व्यापार को ही अपना सबसे बड़ा कर्म समझ रखा है उसके इस कर्म से चीन का खुद भयंकर प्राकृतिक दोहन हुआ है और चीन के कई अंदरूनी हिस्से तबाह हो चुके हैं। चीन ने तो खुद ही उन देशों को यह चेतावनी दे डाली थी कि उसके विकास मॉडल की नकल कोई और देश न करे। लेकिन अफ्रिका के समेत कई देशों को अपने कर्ज के चंगुल में फंसाने के बाद उसने उन गरीब देशों के संसाधनों का भयंकर दोहन किया है। उन्हें बर्बाद किया है।

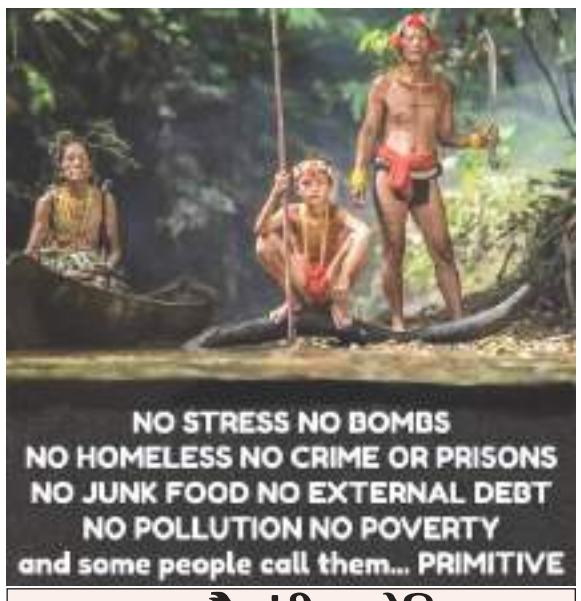

खतरनाक है एंटीबायोटिक्स का अनावश्यक उपयोग

कई शोधों में एंटीबायोटिक दवाओं और किसी रोग के बीच सम्बन्ध को देखा गया है। पर यह पहला मौका है जब किसी शोध में एंटीबायोटिक्स और कई बीमारियों के बीच के सम्बन्ध को देखा गया है। शोध के अनुसार एंटीबायोटिक्स मेटाबोलिज्म से जुड़ी बीमारियों (मोटापा, वजन का बढ़ना), इम्यून से जुड़ी बीमारियों (अस्थमा, फूड एलर्जी, हे फीवर और मानसिक विकार (जैसे एडीएचडी और ऑटिज्म) के खतरे को बढ़ा सकते हैं, हालांकि अलग-अलग एंटीबायोटिक का भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। सेफालोस्पोरिन नामक एंटीबायोटिक कई बीमारियों के जोखिम को बढ़ा देता है, खासतौर पर इसके चलते फूड ऐलर्जी और ऑटिज्म का खतरा काफी बढ़ जाता है।

साथ ही शोधकर्ताओं के अनुसार बच्चों को जितनी कम उम्र में एंटीबायोटिक्स दवाएं दी जाती हैं उनमें उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ता जाता है। विशेष रूप से जब जन्म के शुरुवाती 6 महीनों में बच्चों को एंटीबायोटिक्स किया जाता है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स के ज्यादा और अनावश्यक प्रयोग से बचना चाहिए, जब तक जरुरी न हो इनका प्रयोग बच्चों पर नहीं किया जाना चाहिए।

मांसाहार पर रोक जलवायु संकट का हल नहीं

एजेंसियां

कम मांस वाले आहार करना ठीक है पर इसको पूरी तरह से बंद कर देना जलवायु परिवर्तन का समाधान नहीं है

अमेरिका या यूरोप जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लोगों को आमतौर पर स्वस्थ और कम उत्सर्जन करने का सुझाव दिया जा रहा है। आहार के रूप में मांस और पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को कम खाने को कहा जाता है, लेकिन एक नए शोध में वैज्ञानिकों का तर्क है कि इस तरह की सिफारिशें निम्न या मध्यम आय वाले देशों के लिए नहीं की जा सकती। इन देशों में पशुधन आय और भोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उष्णकटिबंधीय कृषि के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के वैज्ञानिक बिर्थे पॉल ने कहा कि काफी प्रचलित रिपोर्टों से निकाले गए निष्कर्षों का तर्क है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु और मानव स्वास्थ्य के लिए मांस खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन यह तर्क सभी देशों पर लागू नहीं होता।

उदाहरण के लिए 1945 से पशुधन पर प्रकाशित हो रहे सभी वैज्ञानिक साहित्य में से केवल 13 फीसदी ने अफ्रीका को कवर किया है। फिर भी अफ्रीका दुनिया भर में 20 फीसदी मवेशियों, 27 फीसदी भेड़ और 32 फीसदी बकरी आबादी का घर है। पशुधन पर शोध प्रकाशित करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 संस्थानों में से आठ अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड में हैं। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (आईएलआरआई) सहित अफ्रीका में केवल दो मुख्यालय हैं, जहां पशुधन क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर भी उनपर बहुत कम आंकड़े उपलब्ध है।

नोटिनबायबार्ट इंटरनेशनल एंड सीआईएटी के ए नॉटेनबार्ट ने कहा कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मिश्रित व्यवस्था है, जहां पशु उत्पादन पूरी तरह से फसल उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में यह पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ हो सकता है।

उप-सहारा अफ्रीका में खाद एक पोषक तत्व संसाधन है जो मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता को बनाए रखता है। जबकि यूरोप में औद्योगिक तरीके से पशुधन उत्पादन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई भारी मात्रा में खाद कृषि भूमि के लिए जरूरत से ज्यादा है, जो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रही है।अफ्रीका के सवाना के आसपास रात में देहाती भेड़ या मवेशी पालने वाले किसान अपने झुंडों को एकत्रित करते हैं, जो पोषक तत्वों की विविधता और जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र बनते हैं। चारा उत्पादन भी स्थानीय स्तर पर अधिक हो सकता है, जबकि औद्योगिक प्रणालियों में यह ज्यादातर आयात किया जाता है। ब्राजील में सोयाबीन की फसल उगाने के लिए अमेजन वनों की कटाई की जा रही है। इसके बाद इसे वियतनाम और यूरोप में जानवरों को खिलाने के लिए निर्यात किया जाता है।अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान में सस्टेनेबल लाइवस्टॉक सिस्टम के प्रोग्राम लीडर पोली एरिकसेन ने कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थ की तरह जब मांस का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और अधिक व्यवसाय होता है तो इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर कई गुना बढ़ जाता है। एरिकसेन ने कहा कि हमारे आहार से मांस को खत्म करना उस समस्या को हल करने वाला नहीं है। कम मांस वाले आहार करना ठीक है पर इसको पूरी तरह से बंद कर देना जलवायु परिवर्तन का समाधान नहीं है और यह हर जगह लागू नहीं होता है।

खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, उप-सहारा अफ्रीका में 2028 तक प्रति व्यक्ति मांस की खपत औसतन 12.9 किलोग्राम कम होगी। इसके पीछे के कारणों में जानवरों से कम आय और जलवायु संबंधी गर्मी के तनाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे कुपोषण और शरीर का विकास न होना आदि। तुलनात्मक रूप से देखे तो अमेरिका में मांस की प्रति व्यक्ति खपत 100 किलोग्राम से अधिक होने की उम्मीद है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। यह शोध एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने स्वीकार किया कि पशुधन प्रणाली ग्रीनहाउस गैसों का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीति बनाते वक्त निम्न और मध्यम आय वाले देशों से अधिक आंकड़ों की आवश्यकता है।

शोध रिपोर्ट में ऐसे समाधानों की ओर इशारा किया गया, जिनका पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। उनमें से पशु आहार में सुधार हुआ है, इसलिए पशुओं से ग्रीनहाउस गैसों जैसे मीथेन प्रति किलोग्राम दूध या मांस से कम उत्सर्जित होती है। बेहतर ढंग से प्रबंधित भूमि और फसल और पशुधन को मिलाकर जहां खाद मिट्टी में वापस मिल जाती है, किसानों और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचा सकती है।

इनकी बेफ़िक्री घोल रही है आपकी सांसों में ज़हर

आपकी सांसों में जहर घोलने वालों को ट्रैक कर सबके सामने रखने के इरादे से 25 से अधिक पर्यावरण समूह एक साथ एक मंच पर आ गये हैं। और इनके साझा प्रयास से अब ये साफ़ हो रहा है कि दरअसल हमारी सांसों में जहर घोलने के लिए थर्मल पावर प्लांट काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं।

दरअसल बीते कुछ सालों से कोयला बिजलीघरों में उत्सर्जन नियन्त्रण संयंत्रों को लगाये जाने की समय सीमा में लगातार देरी होती जा रही है। डेडलाइन नज़दीक आते ही ये बिजली उत्पादक नई समयसीमा माँग लेते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (टङ्गएउउ) द्वारा नए वायु प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन करने के लिए 2015 में कोयला बिजली कंपनियों को 2 साल की समय सीमा दी गई थी। दिसंबर 2017 तक भारत के 300 कोयला बिजली संयंत्रों को कोयला जलाने पर उत्सर्जन (पार्टिकुलेट मैटर, एसओ 2 और एनओएक्स) को नियंत्रित करने के लिए स्क्रबर्स, फिल्टर और ग्रिप गैस डी-सल्फ्यूरेशन (एफजीडी) तकनीक स्थापित करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एनर्जी एंड एयर (उफ्एअ) द्वारा हाल ही में किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि 2015 के बाद से केवल 1% बिजली संयंत्रों ने ही इन मानदंडों को लागू किया। उस समय के निर्णय की सराहना की गई थी क्योंकि भारत ने अपनी हवा को साफ करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, लेकिन कार्यान्वयन किया जाना था 2017 से 2020 तक, लेकिन देरी होती रही और अब 2022 तक फिर समय की मांग होने लगी है। उम्मीद है कि थर्मल प्लांट्स को यह समय भी मिल ही जाएगा।
इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उफ्एअ के विश्लेषक सुनील दहिया कहते हैं, "बीते पिछले पांच वर्षों को देखते हुए अब समझ यही आता है कि बिजली कंपनियों के दबाव के कारण 2015 की अधिसूचना के तहत सभी मानदंडों को या तो हल्का किया जा रहा है या फिर वो सब कमजोर पड़ने के लिए प्रक्रिया में है। और इस सब का ही नतीजा है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में सिर्फ 2019 में ही वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक जोखिम ने 1.67 मिलियन लोगों की जान ली। साल 2014 में शहरी उत्सर्जन और संरक्षण एक्शन ट्रस्ट द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के परिणामस्वरूप अगले 15 वर्षों में लगभग 229,000 समय से पहले मौतें होंगी।

अपनी मजबूरी और परेशानियाँ बताते हुए, जनवरी 2016 में, पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (एपीपी) ने दावा किया कि प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को पूरा करने के लिए तकनीकी उन्नयन के लिए उन्हें अगले दो वर्षों में क्ष्फ2.4 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। इस आँकड़े पर आपत्ति जताते हुए काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईवी) दावा किया कि असल लागत क्ष्फ90,000 करोड़ के आसपास होगी। आपकी सांसों में ज़हर घोलने वालों को ट्रैक कर सबके सामने रखने के इरादे से 25 से अधिक पर्यावरण समूह ने अ१ङ्कत्रञ्जीर्ली१२.ल्ल के माध्यम से यह साफ़ कर दिया है कि 2015 से अब तक किसने कब प्रदूषण नियंत्रण में ढिलाई बरती है। इस वेबसाइट से यह भी साफ़ होता है कि कैसे थर्मल पावर प्लांट गलत बयानी, बेफ़िक्री, और गैरज़िम्मेदारी के धुंए के गुबार की पीछे छिपे हुए हैं। भारत में हेल्दी एनर्जी इनिशिएटिव सह-समन्वयक श्वेता नारायण कहती हैं, "कोयला बिजली संयंत्र भारत के वायु प्रदूषण संकट के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि थर्मल पावर प्लांट्स के पास रहने वाले लोगों के फेफड़ों पर इन प्लांट्स के उत्सर्जन का गम्भीर असर होता है। लेकिन आत्मानिर्भर भारत का सपना अस्वस्थ भारत की नींव पर नहीं टिक सकता। हर दिन मानदंडों के कार्यान्वयन में देरी के साथ हम बीमारी और विकलांगता वाले अंधकारमय भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

डॉ अरविंद कुमार, संस्थापक ट्रस्टी, लंग केयर फाउंडेशन कहते हैं, "उत्सर्जन मानदंडों में एक एक दिन की देरी हम पर भारी है। हम सबकी जीवन प्रत्याशा इसके चलते कम हो रही है। जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का वक़्त है ये।

क्लाइमेट कहानी से साभार

मानव विकास सूचकांक में एक पायदान लुढ़का भारत

89 देशों की रैंकिंग में 131 वें स्थान पर पहुंचा

मानव विकास सूचकांक की 189 देशों की इस लिस्ट में भारत को 131 वां स्थान दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष (2018 में) भारत को 130 वें स्थान पर रखा गया था

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा इस वर्ष जारी मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स) 2019 में भारत एक पायदान और नीचे पहुंच गया है। 189 देशों की लिस्ट में भारत को 131 वां स्थान दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत इस लिस्ट में 130 वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है। 1990 से लेकर 2019 तक भारत की स्थिति में लगातार सुधार आया है। जहां 1990 में भारत को 0.429 अंक दिए गए थे वो 2019 में बढ़कर 0.645 हो गए हैं। इस अवधि में इस इंडेक्स के मूल्य में 1.42 की वार्षिक औसत से वृद्धि हुई है।

इस श्रेणी में भारत के साथ 36 और देश भी हैं, जिसमें भूटान (129), बांग्लादेश (133), नेपाल (142) और पाकिस्तान (154) जैसे देश शामिल हैं। इंडेक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति श्रीलंका की है जिसे 0.782 अंकों के साथ 72 वें स्थान पर रखा गया है। वहीं मालदीव्स को 95 वें पायदान पर जगह मिली है।
दुनिया में नार्वे की स्थिति सबसे बेहतर है। यही वजह है कि उसे 0.957 अंकों के साथ इस सूचकांक में पहले स्थान पर है।

जल, ऊर्जा और भूमि को वैश्वीकरण ने पहुंचाया नुकसान

एक अध्ययन में पाया गया है कि वैश्वीकरण की वजह से बड़े पैमाने पर जल, ऊर्जा और भूमि संसाधनों पर निर्भर रहने वाले देशों की वैश्विक आपूर्ति सुरक्षा बढ़ने के बजाय घट रही है।अलग-अलग देश घरेलू उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नतीजतन, देश अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इन दबावों को निर्धारित करने के लिए आर्थिक आंकड़ों का उपयोग किया है। उन्होंने पाया कि अधिकांश देशों और औद्योगिक क्षेत्रों को घरेलू उत्पादन के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से आयात के माध्यम से, संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर जल, ऊर्जा और भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

बासमती पर पाकिस्तान के अलावा राज्यों में भी बढ़ी आपसी तकरार

बासमती पर भारत के बाहर और भीतर बढ़ी तकरार, लेकिन किसान हताश
बासमती का जीआई टैग भारत-पाकिस्तान के बीच नाक की लड़ाई बन चुका है, वहीं भारत के अंदर राज्यों में भी तकरार बढ़ रही है

बासमती का जीआई टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लड़ाई का कारण बन गया है। घरेलू स्तर पर लड़ाई मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच है जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत-पाकिस्तान आमने-सामने हैं। पहले बात भारत-पाकिस्तान की लड़ाई की। इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत ने 2018 में अपने बासमती को जीआई टैग दिलाने के लिए यूरोपीय यूनियन के काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल एंड फूडस्टफ्स में आवेदन किया।

पाकिस्तान ने भारत के इस आवेदन को चुनौती देने का फैसला किया है क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो वह बासमती का बड़ा उत्पादक होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन के बाजार से बाहर हो सकता है। अभी पाकिस्तान हर साल एक बिलियन डॉलर का बासमती निर्यात करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों में जाता है। बासमती के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दो-तिहाई है, शेष पर पाकिस्तान का कब्जा है।

जीआई एक विशेष ट्रेडमार्क है जो किसी उत्पाद के मूल स्थान और विशेषताओं को मान्यता देता है। इससे उत्पाद की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस टैग से उत्पाद का विशेष वैश्विक बाजार विकसित होता है और इससे राजस्व प्राप्त होता है। बासमती मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में सिंधु-गंगा के मैदानों में उगाया जाता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 81 जिलों में उगाए जाने वाले बासमती को जीआई टैग दिया है।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार रज्जाक दाऊद ने जीआई टैग के मसले पर 5 अक्टूबर 2020 को वाणिज्य सचिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष, वकीलों और राइस एक्सपोर्ट असोसिएशन से मुलाकात की थी। मीडिया रिपोर्ट्र्स के अनुसार, बैठक में निर्णय लिया गया कि बासमती पर भारत के दावे को चुनौती दी जाएगी। इस मामले में जब पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट असोसिएशन के अध्यक्ष से बात की गयी थी तो उन्होंने यह कहकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला बहुत संवेदनशील है। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस मामले में पाकिस्तानी मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। डॉन मैगजीन ने दाऊद के हवाले से बताया कि पाकिस्तान, भारत के जीआई टैग के दावे का यूरोपीय यूनियन में पुरजोर विरोध करेगा और उसे बासमती की जीआई टैग लेने से रोकेगा।

भारत के दावे को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह यूरोपियन यूनियन में अपना आवेदन जमा करा दिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेश (आईपीओ), पाकिस्तान ने यह आवेदन किया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद के हवाले से यह खबर प्रकाशित की। हालांकि पाकिस्तान की राह मुश्किल बताई जा रही है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के नियमों के तहत पाकिस्तान को अपना जीआई टैग का कानून लागू करना होगा।

पाकिस्तान ने अब तक इस साल मार्च में बने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून को लागू नहीं किया है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि वह जीआई टैग पर चल रहे भारत-पाकिस्तान की लड़ाई से अनभिज्ञ हैं। ऐसा तब है जब सोम प्रकाश बासमती के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब से आते हैं। जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रवीण राव वालचेला बताते हैं कि जीआई टैग के लिए भारत के दावे को डीएनए से मजबूती मिलेगी। यूरोपीय यूनियन में इससे भारतीय दावे को वैज्ञानिक आधार मिलेगा।

डीटीइ से साभार

गोड्डा में 17 धान अधिप्राप्ति केंद्र का चयन किया गया

गोड्डा : जिला आपूर्ति पदाधिकारी ऋतुराज ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में गोड्डा जिलान्तर्गत पूर्व से विभिन्न प्रखंडों में 09 लैम्पस/पैक्स को धान अधिप्राप्ति केन्द्र चयन किया गया है। आवश्यकताओं के अनुरुप खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प सं0-2954 दिनांक-11.11.2020 में निहित निदेश के आलोक में अतिरिक्त धान अधिप्राप्ति केन्द्र के चयन दिनांक- 07.12.2020 को जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया गया है। इस प्रकार खरीफ विपणन मौसम, 2020-21 के लिए 10 लैम्पस/पैक्स एवं 07 ढउ/ढड कुल 17 धान अधिप्राप्ति केन्द्र का चयन किया गया ।

दुमका में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक

दुमका : उपायुक्त रजेश्वरी बी एवं पुलिस अधीक्षक अम्बर लाकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सबसे पहले पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा कीं। उपायुक्त ने कहा कि जिले में अवैध खनन नहीं हो, संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी इसे सुनिश्चित कराएं। कहा कि इन दिनों बालू एवं पत्थर तस्करी को लेकर काफी शिकायतें मिल रही है। जिले के कई प्रखंडों में अवैध खनन का मामला लगातार सामने आ रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। उपायुक्त ने इसके लिए एसडीओ व डीएसपी को अवैध खनन को रोकने के लिए टीम गठित कर छापेमारी तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में आइटीडीए निदेशक राजेश कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य उपस्थित थे।

कांके अंचल में 25 एकड़ सरकारी जमीन घोटाला

संवाददाता

रांची जिले के कांके अंचल स्थित लगभग 25 एकड़ सरकारी जमीन घोटाले मामले की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगी जांच, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी

- **कांके अंचल में 20.59 एकड़ गैर मजरूआ जमीन और जुमार नदी को मिट्टी से भरकर समतलीकरण कर बेचने से जुड़ा है मामला**
- **रांची के उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित जांच रिपोर्ट में कांके अंचल अधिकारी पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप, निलंबित कर कार्मिक विभाग को सेवा वापस करने का किया गया है अनुशंसा**

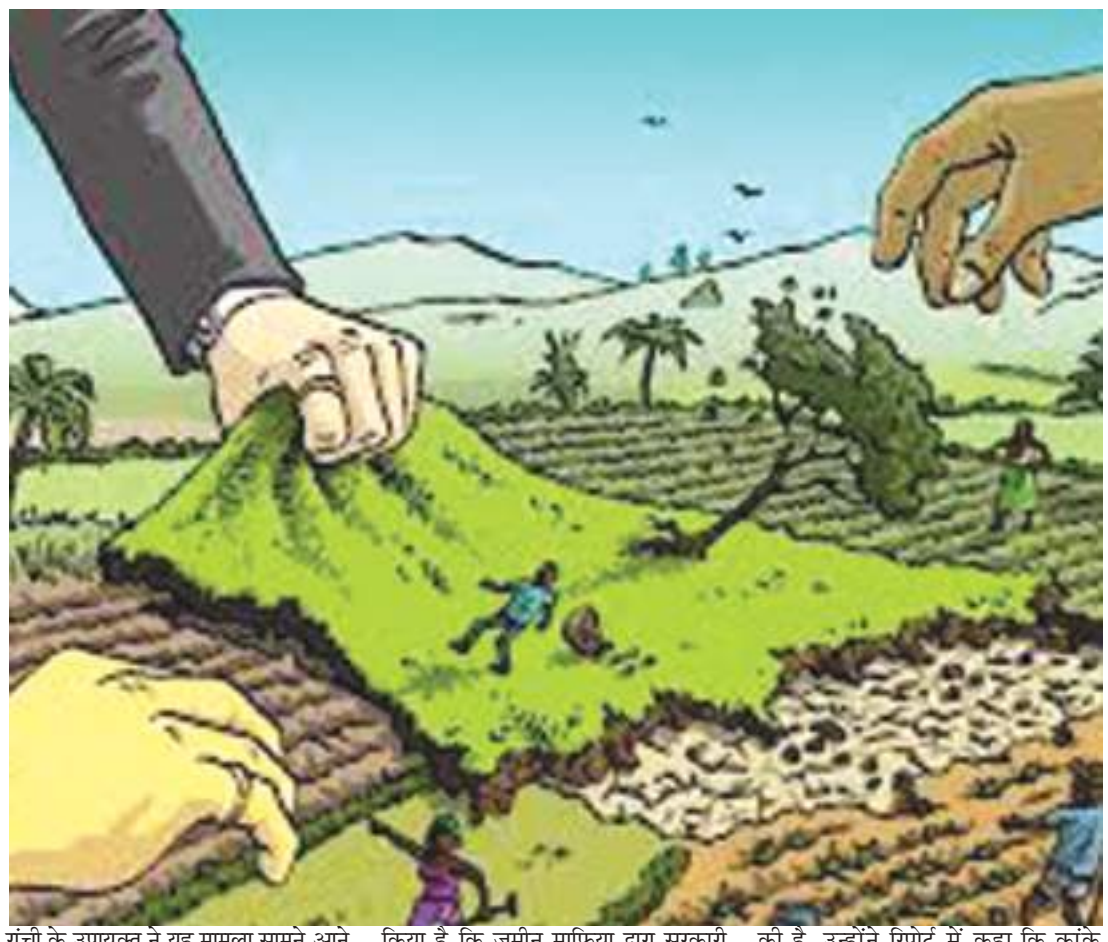

रांची जिले के कांके अंचल स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित जुमार नदी और उसके आसपास के सरकारी जमीन घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को पीई दर्ज कर इसकी जांच करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंजूरी दे दी है. भष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को अधिकतम 45 दिनों के भीतर इस घोटाले की जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा गया है. सरकारी जमीन और जुमार नदी को अतिक्रमित करने तथा बेचने से संबंधित तैयारी में शामिल सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों और जमीन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

मीडिया के जरिए सामने आया मामला

उल्लेखनीय है कि मीडिया के जरिए सरकारी जमीन घोटाले से संबंधित यह मामला सामने आया है. मीडिया ने इस बात को उजागर किया था कि कांके लॉ कॉलेज से सटे रिंग रोड के किनारे करीब 25 एकड़ जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने की तैयारी की जा रही है। साथ ही भू-माफिया द्वारा जुमार नदी के किनारे को मिट्टी डालकर भरने एवं जेसीबी से समतल करने का कार्य किया जा रहा है। यहां लगभग 20.59 एकड़ जमीन गैर मजररूआ प्रकृति की है, जिसमें 20.20 एकड़ भूमि खतियान में नदी के रूप में दर्ज है ।

रांची के उपायुक्त ने यह मामला सामने आने के बाद अपर समाहर्ता, भू हदबंदी से इस-की जांच कराई. अपर समाहर्ता ने जांच के बाद उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यहां की कुछ खाता संख्या के अंतर्गत आने वाले कुछ प्लॉट बकास्त भूइहरी जमीन खतिहान में दर्ज हैं और खाता संख्या 142 प्लॉट संख्या 2309 गैर मजरुआ मालिक प्रकृति की भूमि है, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अर्जित है. साथ ही लगभग 20.59 एकड़ जमीन गैर मजरुआ मालिक प्रकृति की है. नदी के रुप में दर्ज 20.20 एकड़ जमीन के अंश भग पर रिवर व्यू गार्डेन के प्रोपराइटर कमलेश कुमार द्वारा मिट्टी भरवाकर समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है.

कांके अंचल अधिकारी की संलिप्तता

उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा इस जमीन घोटाले की कराई गई जांच रिपोर्ट भू राजस्व विभाग को सौंपा. इसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि जमीन माफिया द्वारा सरकारी जमीन के अतिक्रमण में कांके अंचल के अंचल पदाधिकारी की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है. सरकारी जमीन का संरक्षण होने के बावजूद भी अंचल अधिकारी द्वारा सरकारी जमीन और नदी को भरने के मामले को नजरअंदाज करना कहीं न कहीं उनके शामिल होने को इंगित करता है. इतना ही नहीं, कांके अंचल अधिकारी द्वारा इस साल 10 नवंबर को ई- मेल के माध्यम से प्रतिबंधित भूमि की जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उसमें उपरोक्त सरकारी भूमि को प्रतिबंधित सूची में नहीं डाला गया है, जिसमें भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है.

अंचल अधिकारी को निलंबित करने की अनुशंसा

उपायुक्त ने प्रतिवेदित रिपोर्ट के माध्यम से कांके के अंचल अधिकारी श्री अनिल कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि कांके अंचल अधिकारी से इस जमीन घोटाले के मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है. यह उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुश-ासनहीनता और उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना है. अतः कांके अंचल अधिकारी को निलंबित करते हुए उनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को वापस की जा सकती है.

त्वरित अनुसंधान कर संलिप्त सरकारी कर्मियों और जमीन दलालों पर हो कठोर कार्रवाई

उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट में दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित अनुसंधान करते संलिप्त पदाधिकारी, कर्मी और जमीन दलालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने एसीबी को पीई दर्ज कर जांच रिपोर्ट देने को कहा है।

विश्व में 270 करोड़ लोग कोरोना के कारण हुये लाचार, असहाय

दुनिया की एक तिहाई आबादी या 270 करोड़ लोग कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट से निपटने में असहाय हैं, क्योंकि इससे उबरने के लिए उनके पास कोई सरकारी सहायता नहीं है यह जानकारी गैर लाभकारी संगठन ऑक्सफेम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 'शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म' में सामने आई है।

भारत सहित 126 निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है इन योजनाओं का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के दौरान विकलांगों, बुजुर्गों, बेरोजगारों और बच्चों को महामारी के दौरान आर्थिक मदद देना थो पता चला है कि उनमें से कोई भी देश अपने सभी लोगों की मदद करने में सफल नहीं रहा था।

रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए दुनिया ने इस वर्ष करीब 8,61,22,413 करोड़ रुपए (11,70,000 करोड़ डॉलर) का अतिरिक्त खर्च किया है इनमें से करीब 83 फीसदी (7,21,36,722 करोड़ रुपए) 36 अमीर देशों ने खर्च किए हैं जबकि इसके विपरीत केवल 0.4 फीसदी (3,09,157 करोड़ रुपए) गरीब देशों द्वारा खर्च किए गए हैं जहां एक ओर अमीर देशों ने प्रति व्यक्ति 51,158 रुपए की दर से खर्च किया था, वहीं इसके विपरीत निम्न और माध्यम आय वाले देशों ने प्रति व्यक्ति केवल 294 से 2061 रुपए (4 से 28 डॉलर) के बीच खर्च किया था।

परेशानी के इस वक्त में विकसित देशों ने भी विकासशील देशों की कोई ख़ास मदद नहीं की थी अमीर देशों ने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 42,693 करोड़ रुपए (580 करोड़ डॉलर) की मदद दी थी यह राशि कोविड-19 से निपटने के लिए खर्च किए हर 100 डॉलर के पांच सेंट के बराबर हिस्से से भी कम है। ऑक्सफैम की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर के अनुसार, "एक ओर जहां कोरोनोवायरस के डर ने सारी दुनिया को एकजुट कर दिया है, लेकिन जब बात उसका सामना करने की है तो हर कोई अपने बारे में सोच रहा है" उनके अनुसार जहां 2020 में इस महामारी के चलते 100 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी गई, वहीं इससे कहीं ज्यादा लोगों को पीछे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था।

ऐसे में एक बात तो साफ है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली योजनाओं की बहुत ज्यादा जरुरत है इस महामारी के चलते करीब 50 करोड़ लोगों से उनका काम छिन चुका है जिसमें पुरुषों के मुकाबले दो गुना महिलाएं हैं गरीब देशों के श्रमिकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है दुनिया भर में लोग कर्ज में डूब चुके हैं, उन्हें अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ी थी यहां तक की कई परिवारों को अपना एक बार का खाना भी छोड़ना पड़ा थो परिवार के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है जिस वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा है दुनिया भर में गरीबी और भुखमरी पहले के मुकाबले और बढ़ गई है

अब तक भारत सहित दुनिया के 218 देशों में फैल चुका है, अब तक इसके करीब 7.5 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं वहीं इसके चलते 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है भारत में भी इस महामारी के 99,56,557 मामले सामने आ चुके हैं जब कि यह बीमारी 144,451 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है।

राज्य में धान क्रय केंद्र की संख्या बढायें: मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो। इसके लिए पूरे राज्य में धान संग्रह केंद्रों की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाएं। धान क्रय करने तैयारी पूर्व से प्रारंभ होना चाहिए, जिससे धान क्रय करने और उसके संग्रहण में दिक्कत न हो। चलंत क्रय केंद्र, हाट-बाजार में क्रय करने की योजना पर भी विभाग विचार करे। उदेश्य स्पष्ट है किसानों की सहूलियत के अनुरूप धान क्रय करना।

मत्स्य पालन के दायरे में बढ़ोतरी करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि चांडिल डैम में बड़ा केज कल्चर नजर आता है। अन्यथा अधिकतर जगह छोटे स्तर पर मत्स्य का उत्पादन हो रहा है। विभाग मत्स्य उत्पादन में और बढ़ोतरी करे। पशुधन का लाभ सभी प्रमंडल के लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार मिले, तो वे लाभान्वित होंगे। विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये।

ससमय उपलब्ध हो सके बीज-खाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग बजट का रिस्ट्रक्चर करे, जिससे समय पूर्व तैयारी कर किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। ससमय बीज, खाद व अन्य कृषि से संबंधित संसाधनों का क्रय सुनिश्चित हो सके। किसानों को सरसों, दलहन, सोयाबीन की खेती के लिए जागरूक करें, जिससे उनके अधिक से अधिक आर्थिक लाभ की राह आसान हो। इनके उत्पादन से किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

चना बीज का वितरण किया गया

- **जरमुंडी प्रखंड के नौनी गाँव मे किया गया चना बीज का वितरण**
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत किया गया बीज वितरण... 78 किसानों के बीच चना बीज का किया गया वितरण**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत प्रत्यक्षण के लिए जरमुंडी प्रखंड के नौनी गांव में 7 हेक्टेयर का संकुल बनाकर कृषकों के बीच चना बीज का वितरण किया गया। प्रति एकड़ 3 किलो बीज के अनुपात में चना बीज का वितरण किया गया।जरमुंडी प्रखंड के नौनी गांव में बीज वितरण कार्यक्रम के दौरान कुल 78 किसानों के बीच चना बीज का वितरण किया गया।परियोजना निदेशक आत्मा देवेश कुमार सिंह ने बताया कि टीआरएफए योजना अंतर्गत पूरे जिले में 1800 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जिसका बीज प्रखंडों में जाना प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंडों को निदेशित किया गया है कि कलस्टर बनाकर लाभुक कृषकों की सूची तैयार रखें तथा बीज पहुंचते ही लाभुकों के बीच बीज का वितरण करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर कृषि मंत्री के प्रतिनिधि सहित किसान मित्र तथा बड़ी संख्या में लाभुक उपस्थित थे।

मुरी स्टेशन पर संरक्षा बैठक का आयोजन

संवाददाता :नौ दिसंबर को मुरी स्टेशन में अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित की पस्थिति में संरक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस संरक्षा बैठक में परिचालन , संरक्षा, मेकेनिकल, विद्युत एवं इंजीनियरिंग विभाग के वे सभी कर्मचारी उपस्थित थे जो परिचालन में संरक्षा से संबंधित तकनीकी कार्य करते हैं।

इस बैठक में मुख्यतः हॉट एक्सल, ट्रेनों का जीडीआर चेक, तथा ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की सजगता विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई, परिचालन के दौरान ट्रेन के ड्राइवर एवं गार्ड के साथ ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना, स्टेशन से पास करती हुई गाड़ियों को ध्यान से देखना विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) ने संरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सतर्क व्यक्ति ही संरक्षा का सर्वोत्तम साधन हैं ड्यूटी के दौरान कर्मचारी सजग रहें एवं संरक्षा के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें और परिचालन में

किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। बैठक में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता पंकज कुमार , मंडल संरक्षा अधिकारी श्री कविंद्र चौधरी, मंडल विद्युत अभियंता श्री दीपांजल सरकार, मंडल अभियंता (पूर्व) विश्वजीत घोष, सहायक परिचालन प्रबंधक विभूति नारायण शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किया।

बैठक में मुरी तथा आसपास के स्टेशनों के लगभग 100 कर्मचारियों ने भाग लिया उपस्थित कर्मचारियों से भी उनके कार्य मे सुगमता लाने हेतु परामर्श लिए गए ।

जलवायु के आंकड़ों से हैजा के प्रसार का पूर्वानुमान में होगी मदद

एजेंसियां

पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से लिए गए जलवायु आंकड़े, मशीन लर्निंग तकनीक के साथ मिलकर, हैजा के प्रकोप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं

जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में महासागरीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र में जटिल पर्यावरणीय परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन पानी से फैलने वाले अथवा जलजनित रोगों में भी बदलाव ला रहे हैं। इनकी जीवित रहने की दर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है। इनमें से एक हैजा है जो प्रदूषित पानी से होने वाला रोग है, यह जीवाणु विब्रियो कॉलेरी से दूषित पानी या दूषित भोजन करने के कारण होता है। यह बीमारी अक्सर दुनिया भर के कई तटीय क्षेत्रों में होती है, विशेष रूप से घनी आबादी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। रोग फैलाने वाला यह जीवाणु आम तौर पर गर्म तापमान, कम खारे पानी और जहां गंदगी होती है वहां पाया जाता है। यह पानी में अति-सूक्ष्म जीव (प्लवक) और कचरे में रहते हैं।

पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से लिए गए जलवायु आंकड़े, मशीन लर्निंग तकनीक के साथ मिलकर, हैजा के प्रकोप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। एक बार प्रकोप के बारे में पता लगने पर लोगों की जान बचाने में यह कारगर सिद्ध हो सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि से हैजा का प्रकोप बढ़ रहा है। एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में हर साल 13 लाख से 40 लाख लोगों को प्रभावित करती है और इसके कारण लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। एक नए अध्ययन के अनुसार भारत के तटीय क्षेत्रों में हैजा का पूर्वानुमान लगाने के लिए समुद्री सतह के खारेपन का उपयोग किया गया। प्रकोप का पता लगाने की सफलता दर 89 फीसदी तक थी।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित शोध उत्तरी हिंद महासागर के आसपास हैजा के प्रकोप का पूर्वानुमान लगाने पर केंद्रित है। जहां 2010-16 की अवधि में दुनिया भर में हैजे की बीमारी के मामलों में से आधे से अधिक मामले सामने आए थे। हैजे की बीमारी की घटना और पर्यावरण के बीच जटिल संबंध हैं और मौसमी आधार पर इस-के रूप अलग-अलग होते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन आंकड़ों की मदद से परीक्षण योग्य अनुमान लगाने के लिए बड़े डेटासेट में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। इस अध्ययन का नेतृत्व एमी कैंपबेल द्वारा किया गया था। कैंपबेल यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) जलवायु कार्यालय के साथ एक साल तक स्नातक प्रशिक्षु रहे। एमी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्लायमाउथ मरीन लेबोरेटरी (पीएमएल) में पर्यावरण विज्ञान के प्रयोगों में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया। यह एल्गोरिदम लंबे डेटासेट में पैटर्न को पहचान सकता है और परीक्षण योग्य अनुमान लगा सकता है। एल्गोरिदम को 2010 और 2018 के बीच भारत के तटीय जिलों में दर्ज किए गए रोग के प्रकोपों के आधार पर प्रशिक्षित किया गया था और ईएसए के जलवायु परिवर्तन पहल (सीसीआई) द्वारा उत्पन्न छह उपग्रह-आधारित जलवायु रिकॉर्ड के साथ संबंधों की पहचान की।

पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चीजों को शामिल कर तथा हटाकर अलग-अलग मौसमों के अनुसार इसमें छोटे-छोटे बदलाव किए गए। एल्गोरिथ्म ने हैजा के प्रकोप को भूमि की सतह के तापमान, समुद्र की सतह के खारेपन, क्लोरोफिल की एकाग्रता और समुद्र स्तर में औसत अंतर के रूप में पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव की पहचान की।

एमी कैंपबेल ने कहा कि मॉडल ने आशाजनक परिणाम दिखाए और विभिन्न हैजा निगरानी के डेटासेट या अलग-अलग स्थानों का उपयोग करके इस काम को और सुधार करने की गुंजाइश है। हमारे अध्ययन में, हमने विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीकों का परीक्षण किया। यह सबसे अच्छा है, लेकिन अभी और तकनीकें हैं जिनकी जांच की जा सकती है।सामाजिक-आर्थिक डेटासेट सहित इन पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण करना दिलचस्प होगा। रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग से रिकॉर्ड तैयार किए जा सकते है, जो हैजा की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इसके जल संसाधनों तक पहुंच जाना, इसमें लोग किस तरह की भूमिका निभाते है इस पर भी जानकारी मिल सकती है।

अध्ययन और इसकी नई जानकारियों ने पीएमएल के शोधकर्ता मैरी-फैनी रौल्ट की अगुवाई में कोलरा एंड सॉल्यूशन टूल्स प्रोजेक्ट के लिए यूकेआरआई-एनईआरसी में योगदान दिया है, जो आवासों पर जलवायु की चरम सीमाओं के प्रभाव का आकलन कर रहा है, जो हैजे का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयुक्त है।

फोटो न्यूज

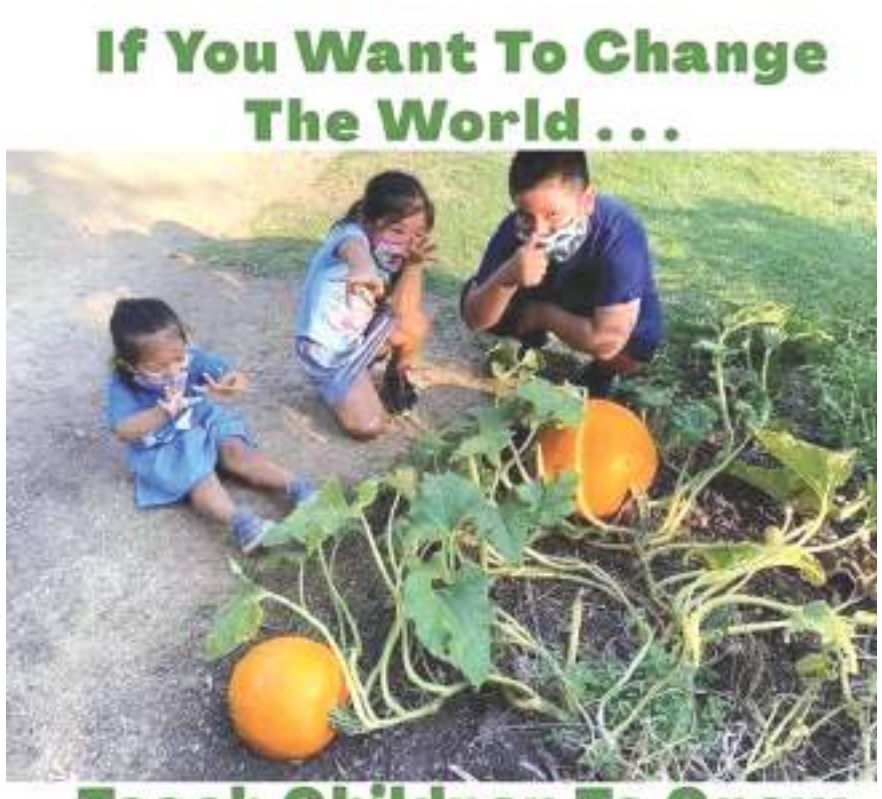

इस फोटो सेशन के क्या कहने?

डायबिटीज रोगियों के लिए ज्यादा खतरनाक है कोविड-19

कोविड-19 के साथ-साथ टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा तीन गुना ज्यादा होता है

एक हालिया शोध से पता चला है कि जिन मरीजों को टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के साथ-साथ कोविड-19 है, उनके गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ती है। यह शोध जर्नल डायबिटीज केयर में प्रकाशित हुआ है।

इसे समझने के लिए वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 614,113 मरीजों के स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इनमें से 613,840 रोगी सिर्फ कोविड-19 से ग्रस्त थे, जबकि 273 मरीज कोविड-19 के साथ-साथ टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह से भी ग्रस्त थे। शोध के अनुसार जिन मरीजों को टाइप 1 डायबिटीज के साथ कोविड-19 भी है उनके अस्पताल में भर्ती होने की सम्भावना, केवल कोविड-19 से ग्रस्त मरीजों की तुलना में 3.9 गुना ज्यादा होती है। साथ ही उनके कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार होने की सम्भावना 3.35 गुना ज्यादा थी। अध्ययन के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज रोगियों में कोविड-19 का जोखिम कहीं ज्यादा होता है। जिसका मतलब था कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ-साथ कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के गंभीर रूप से बीमार होने की सम्भावना कम से कम तीन गुना ज्यादा थी। साथ ही बिना डायबिटीज वाले लोगों की तुलना में उनके अस्पताल में भर्ती होने की सम्भावना कहीं ज्यादा थी।

इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता जस्टिन ग्रेगोरी के अनुसार विश्लेषण से पता चला है कि टाइप 1 या टाइप 2 मधुमेह रोगियों में कोविड-19 से गंभीर रूप से ग्रस्त होने का खतरा कहीं ज्यादा है यही वजह है कि हृदय और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त लोगों की तरह ही मधुमेह से ग्रस्त रोगियों पर भी विशेष ध्यान देने की जरुरत है। साथ ही उनके टीकाकरण की जरुरत भी ज्यादा है।

शोध के अनुसार जो रोगी अपने मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए बेहतर तकनीक का उपयोग करते हैं, उनके गंभीर रूप से बीमार होनी की सम्भावना कम थी। साथ ही अध्ययन के अनुसार उम्र, वंश और अन्य कारक भी उसपर असर डालते हैं।टाइप 1 डायबिटीज रोगियों पर कोविड-19 कितना गंभीर असर डालेगा यह ग्लाइसेमिक, वस्कुलर और सामाजिक-आर्थिक जोखिमों पर भी निर्भर करता है। यदि रोगियों को कोविड-19 के साथ टाइप 1 डायबिटीज है तो रोगी के मरने की सम्भावना 3.5 गुना ज्यादा थी। जबकि यदि उसे टाइप 2 डायबिटीज है तो यह सम्भावना दो गुना ज्यादा है। इस मामले में विशेषज्ञों को चिंता है कि कोविड-19 का प्रसार सर्दियों में बहुत अधिक बढ़ जाएगा और मधुमेह से ग्रस्त मरीजों को यह कहीं ज्यादा प्रभावित करेगा। तापमान में गिरावट के साथ-साथ, लोग घरों में रहने को मजबूर हो जाएंगे, आर्द्रता में कमी आएगी और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा।

पिछले अध्ययनों से पता चला है कि सर्दियों के मौसम में जब तापमान में गिरावट आती है और ठंड बढ़ती है तो उसके साथ-साथ कमरे में सापेक्ष आर्द्रता भी कम हो जाती है। फ्लू से जुड़े वायरस ऐसे समय में आसानी से जीवित रहते हैं और ठंडी और शुष्क हवा में अधिक आसानी से प्रसारित होते हैं। यह बात सार्स-कोव-2 वायरस पर भी लागु होती है, जिसकी संरचना और आकर भी फ्लू वायरस के समान ही होती है।

वर्ष 2020-21 के बजट की जानकारी ली

संवाददाता

रांची :मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से अवगत हुए। उन्होंने कृषि, पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य और सहकारिता विभाग के केंद्र व राज्य प्रयोजित योजनाओं में किये गए आवंटन की जानकारी ली। उपरोक्त सभी विषयों की योजनाओं की संख्या जानी, इनमें केंद्र व राज्य की योजनाएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने केंद्र एवं राज्य की योजनाओं प्रदर्शन, मुख्य योजनाओं की स्थिति और आगे की विभागीय योजना, राज्य की नई योजनाओं की कार्य योजना, मुख्य गतिविधियों और उपलब्धि, विभाग में मानव संसाधन की स्थिति, रिक्त पदों को भरने के विरुद्ध उठाये गए कदम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जानकारी ली।

बैठक में मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अबू बकर सिद्दिकी, निदेशक गव्य विकास कृपानंद झा, निदेशक कृषि श्रीमती निशा उरांव, निदेशक कोऑपरेटिव मृत्युंजय कुमार वर्णवाल, निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन वरुण रंजन, निदेशक पशुपालन श्रीमती नैंसी सहाय व विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

दक्षिण एशियाई देशों में केवल 13 फीसदी स्कूली बच्चों के घर पर है इंटरनेट की सुविधा: यूएन

एजेंसियां

एक रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले देशों के 20 से कम आयु वर्ग के अधिकतर बच्चों में से एक के पास घर पर इंटरनेट की सुविधा थी, जबकि अमीर देशों में यह 10 में से 9 बच्चों के पास थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में दो-तिहाई (220 करोड़) स्कूली बच्चों के पास घर में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, महामारी की वजह से स्कूल बंद हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा तक पहुंच महत्वपूर्ण हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) की संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन से 17 साल के बीच के अनुमानित 130 करोड़ बच्चों के घरों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार घर पर रहने वाले 15 से 24 वर्ष के 63 फीसदी युवाओं के पास इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा नहीं है।

यूनिसेफ के प्रमुख हेनरिटा फोर ने कहा इतने सारे बच्चों और युवाओं के पास घर में कोई इंटरनेट नहीं है जो एक तरह से डिजिटल खाई में बढ़ोत्तरी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में कमी युवाओं को आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है तथा उन्हें दुनिया में अलग-थलग करता है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष विशेष रूप से चिंताजनक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए हैं, लाखों छात्र वर्चुअल लर्निंग पर आश्रित रहने के लिए मजबूर हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो इंटरनेट का अभाव अगली पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में डाल सकता है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि महामारी से पहले भी, डिजिटल विभाजन असमानताओं को बढ़ावा दे रहा था, जिससे सबसे गरीब घरों और ग्रामीण या निम्न-आय वाले देशों के बच्चों को आगे बढ़ने के बहुत कम अवसर मिलते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले देशों के 20 से कम आयु वर्ग के अधिकतर बच्चों में से एक के पास घर पर इंटरनेट की सुविधा थी, जबकि अमीर देशों में यह 10 में से 9 बच्चों के पास थी।

लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं खाना पकाने से होने वाले प्रदूषण के कण

एजेंसियां

अध्ययन में बताया गया है कि खाना पकाने के दौरान उत्सर्जित होने वाले कण एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, वे अन्य प्रदूषक कणों को भी शामिल कर सकते हैं खाना पकाने से होने वाला उत्सर्जन वायुमंडल में लंबे समय तक रहता है, जिसके कारण हवा की गुणवत्ता खराब होती है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है।

शहरी वायु प्रदूषण में पार्टिकुलेट मैटर की अहम भूमिका होती है। कार्बनिक पदार्थ शहरी एरोसोल के एक बड़े हिस्से में फैले होते हैं।यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के शोधकर्ताओं ने यह करके दिखाया कि किस तरह खाना पकाने के दौरान होने वाले उत्सर्जन से निकलने वाले कण (पार्टिकुलेट मैटर) प्रदूषण वातावरण में फैल जाते हैं। अलग-अलग देशों, शहरों में इनका अनुपात अलग है, जैसे ब्रिटेन के वातावरण में इनका अनुपात 10 प्रतिशत तक है वहीं चीन में 22 प्रतिशत है। इन कणों के टूटने और फैलने के बजाय ये कई दिनों तक वायुमंडल में बने रहते हैं। टीम ने बाथ विश्वविद्यालय, सेंट्रल लेजर फैसिलिटी और डायमंड लाइट सोर्स के विशेषज्ञों के साथ मिलकर यह दिखाया कि ये फैटी एसिड अणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अणुओं के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया के दौरान कण के बाहर एक कोटिंग या क्रस्ट बनता है जो ओजोन जैसी गैसों के अंदर फैटी एसिड की रक्षा करता है जिससे कण टूटते नहीं हैं।

यह पहली बार है जब वैज्ञानिक इस तरह से प्रक्रिया को बनाने में सफल हुए हैं, प्रयोगशाला में डायमंड लाइट सोर्स पर शक्तिशाली एक्स-रे बीम का उपयोग करके खाना पकाने के दौरान अणुओं की पतली परतों से हर मिनट होने वाले उत्सर्जन का अध्ययन किया गया। इन कणों की वायुमंडल में रहने की क्षमता ने जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के लिए कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। क्योंकि अणु पानी के साथ इतने नजदीक होते हैं, इससे बादल बनाने वाले पानी की बूंदों की क्षमता प्रभावित होती है। बदले में यह वर्षा की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है, और सूरज की रोशनी की मात्रा को भी प्रभावित करते है जो सभी तापमान के परिवर्तन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। खाना पकाने के दौरान उत्सर्जित होने वाले कण एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, वे अन्य प्रदूषक कणों को भी शामिल कर सकते हैं, जिनको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है जैसे कि डीजल इंजन से उत्सर्जित होने वाले कैंसर कारक कार्सिनोजन आदि। ये कण बहुत लंबे क्षेत्र में पहुच सकते हैं। यह अध्ययन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फैराडे डिस्कशन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

बर्मिंघम विश्वविद्यालय के भूगोल, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान के प्रमुख लेखक डॉ. क्रिश्चियन पफ्रांग ने कहा कि ये उत्सर्जन, जो विशेष रूप से खाना पकाने की प्रक्रियाओं से होते हैं, जैसे कि अधिक वसा जमने, शहरों में वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण अनुपात है, विशेष रूप से छोटे कणों में जिन्हें पीएम 2.5 कणों के रूप में जाना जाता है। लंदन के वातावरण में इन कणों की मात्रा लगभग 10 प्रतिशत है, लेकिन चीन में हाल ही में मात्रा 22 प्रतिशत थी जबकि हांगकांग में इनकी मात्रा 39 प्रतिशत तक दर्ज की गई हैं। शहर की योजना बनाने में सुझावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन हमें उन तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए जो हवा को साफ करने तरीकों को नियमित कर सकते हैं।

किसान क्यों नहीं बनाते टमाटर से सूप पाउडर?

निशांक चौधरी

किसानों के लिए ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता है
किसानों को फसल उगाने के बाद वेल्यू एडिशन का प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता।

पिछले 74 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में तो काफी सुधार देखने को मिला है, परंतु किसान के हालात में नहीं। इसका मुख्य कारण जमीनी स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नीतियों का ढंग से लागू नहीं करवा पाना रहा है। जब टमाटर का रेट 2 रुपए किलो होता है, तो किसान उसे सड़कों पर फेंक देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वह इस टमाटर को इतने कम दाम पर मंडी में बेचने गया तो वह उल्टा अपने सिर कर्जा चढ़वा बैठेगा।

हर पंचायत में थी एक उन्नत ग्राम बाजार बनाने की सिफारिश, तीन साल बीत रहे अभी सर्वे जारी
गांव के 22 हजार हाट बाजारों में अब तक सिर्फ 476 को किया जा सका अपग्रेड

परन्तु इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसान को इस बात की जानकारी नहीं है कि वह इस टमाटर का वैल्यू एडिशन करके अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बना सकता है जैसे टोमेटो सूप पाउडर, केचप और इन्हें मार्केट में बेचने पर टमाटर की फसल से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 जो कि डीसेंट वर्क और इकोनामिक ग्रोथ की बात करता है उसे भी अपने साथ जोड़ सकता है , परन्तु हकीकत यह है कि किसान इस काम को करने में आने वाली लागत और बाजार संबंधित समस्याओं के बारे में सोचकर ही अपना मन मारकर बैठ जाता है इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि किसानों को न तो उनकी ग्राम पंचायत और ना ही क्षेत्रीय अधिकारियों ने उनके बीच में जाकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्राइम मिनिस्टर एंप्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कार्यक्रम जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आते है के बारे में बातकर इन्हे इससे जुड़ने के लिए प्रेरित और जागरूक नहीं किया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार न सिर्फ ग्राम्य उद्यमिता (रूरल एंटरप्राइज) में रुचि रखने वाले लोगों को ट्रेनिंग देती है, बल्कि फंड मुहैया कराने से लेकर प्रोजेक्ट तैयार करने में भी पूरा सहयोग करती है।आज की वर्तमान परिस्थितियों में रूरल एंटरप्राइज ही एक ऐसा साधन बचा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद करेगा और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे शहरी पलायन को भी रोकेगा। साथ ही कोरोना जैसी महामारी ने भी हमें यह बता दिया कि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना कृषि अर्थव्यवस्था के बिना नहीं की जा सकती है।

निशांक चौधरी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार) के छात्र हैं

जलवायु परिवर्तन और विकास लक्ष्यों का तालमेल जरूरी

अध्ययन में पाया गया कि यदि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 10 हजार डॉलर से अधिक हो जाए तो देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे 0.3 डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त तापमान कम होगा। आर्थिक विकास कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2) उत्सर्जन में वृद्धि करता है। विशेष रूप से उभरते हुए देशों जैसे चीन, भारत और ब्राजील के कुछ अध्ययनों से पता चला है कि आर्थिक गतिविधि के दौरान कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता बाद के चरणों की तुलना में विकास के शुरुआती चरणों में अधिक होती है।

अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस और कनाडा के वाटरलू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन और विकास लक्ष्यों के बीच सामंजस्य को लेकर एक अध्ययन किया है। अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तभी कम होगा, जब विकास की प्रक्रिया में विकासशील देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों की गति को, तब तक धीमा करना होगा जब तक कि वे आर्थिक विकास के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाते हैं।

अध्ययन में जलवायु परिणामों की जांच की गई है, जिसमें कहा गया है कि विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के एक विशेष स्तर तक पहुंचना चाहिए। विश्व बैंक से सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या के आंकड़ों को मिलाकर सीओ 2 उत्सर्जन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए, वाटरलू विश्वविद्यालय से जुआन मोरेनो-क्रूज के साथ कार्नेगी इंस्ट-ीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिकों लेई डुआन और केन कैलेडेरा ने एक विस्तृत श्रृंखला बनाई है। जो भविष्य के परिदृश्यों जिसमें सीओ 2 उत्सर्जन ऐतिहासिक रुझानों के अनुसार बढ़ता है और फिर इसमें केवल तभी गिरावट शुरू होती है जब देश एक विशेष आय स्तर तक पहुंच जाते हैं।

लेई डुआन ने कहा कि कम विकसित देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन कम (डीकार्बोना-इजेशन) करना अक्सर प्राथमिकता तब तक नहीं होती है, जब तक कि वे आर्थिक विकास और ऊर्जा सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित नहीं करते। जैसा कि ये देश विकास और समृद्धि की दिशा में काम करते हैं, उन्हें जलवायु और विकास लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर विकासशील देश अपने सीओ2 उत्सर्जन को कम करने के उपायों को अपनाने में देरी करते हैं, तो हमें यह जानना होगा कि इसका जलवायु पर क्या प्रभाव होगा।

अध्ययन में पाया गया कि यदि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 10 हजार डॉलर से अधिक हो जाए तो देशों को कार्बन उत्सर्जन कम (डीकार्बोनाइजेशन) करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे 0.3 डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त तापमान कम होगा। जिन देशों का जीडीपी स्तर ऊपर है यदि वे देश प्रति वर्ष 2 फीसदी की दर से उत्सर्जन को कम करते हैं, तो विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए और समय मिलेगा जोकि 2020 और 2100 के बीच कुल सीओ 2 उत्सर्जन का केवल लगभग 6 फीसदी होगा।

वाटरलू विश्वविद्यालय से जुआन मोरेनो-क्रूज ने कहा कि वर्तमान में दुनिया की आधी से अधिक आबादी 10 हजार डॉलर की आय सीमा से नीचे वाले देशों में रहती है, फिर भी हमारे अध्ययन से पता चलता है कि इन देशों में कार्बन उत्सर्जन कम (डीकार्बोनाइजेशन) करने में भागीदारी की कमी का वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत तापमान में बदलाव पर कम प्रभाव पड़ेगा। यह अध्ययन एनवायर्नमेंटल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

हालांकि अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि लंबी अवधि के उत्सर्जन वाली तकनीक (एमिशन एमिटिंग टेक्नोलॉजी) को लागू करने से बचा जाना चाहिए। चुनौती यह सुनिश्चित करने के की है आज जीवाश्म ईंधन में किए गए निवेश एक बुनियादी ढांचा नहीं बनाते हैं, जिससे कम कार्बन वाला भविष्य बनाना संभव नहीं है।

कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के केन कैल्डिरा बताते हैं कि खतरा इस बात का है कि कम-विकसित देश जीवाश्म-ईंधन के उपयोग के आदी हो जाते हैं और उनके लिए इस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इससे उनका विकास होता है। आधुनिक और कम कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास को जगह मिलनी चाहिए।

लेई डुआन कहते हैं कि हम मानते हैं कि सभी देशों को तापमान बढ़ने की पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है जो 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा में रहे। लेकिन इस अध्ययन से पता चलता है कि परिदृश्यों और मान्यताओं की एक विस्तृत श्रृंखला में, अधिक से अधिक प्रभाव मध्यम और उच्च आय वाले देशों के डीकार्बोनाइजेशन से आएगा।

निशांत सक्सेना द्वारा प्रेषित

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।